भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1789

4 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: मंत्रालय के उद्देश्य

1789. श्री कपिल सिब्बल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस मंत्रालय के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) चूंकि सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय है। तो ऐसे में मंत्रालय का क्षेत्राधिकार क्या है; और

(ग) क्या सरकार सहकारी समितियों में निजी निवेश शुरू करने के तरीकों पर कार्य कर रही है?

उत्तर

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): सहकारिता मंत्रालय का अधिदेश और अधिकार क्षेत्र भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार है। आवंटित विषय **अनुबंध- I** के अनुसार हैं।

(ग): जी नहीं।

अनुबंध-1

1. सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य नीति और सभी क्षेत्रों में सहकारिता गतिविधियों का समन्वय ।

नोट:- संबंधित मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों में सहकारिता के लिए उत्तरदायी हैं।

2. "सहकारिता से समृद्धि की ओर" दृष्टि की प्राप्ति।

3. देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करना।

4. देश के विकास के लिए अपने सदस्यों के बीच जिम्मेदारी की भावना सहित सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना।

5. सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत ढांचे का निर्माण।

6. राष्ट्रीय सहकारी संगठन से संबंधित मामले।

7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

8. 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न होने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन:

बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।

9. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण (सदस्यों, पदाधिकारियों और गैर-अधिकारियों की शिक्षा सहित)।

******